कानपुर, बुधवार, 17 जून, 2026
वर्ष: 03, अंक: 148, पृष्ठ: 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com
Website: www.swarajindianews.com

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड ट्रंप पर बड़े हमले की साजिश नाकाम...>Pg03

केडीए का बड़ा बुलडोजर एक्शन...>Pg12

मूल्य: 2 ₹

पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम पर लगा बैन

पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना अनुपातहीन कदमः टेलीग्राम

NATIONAL TESTING AGENCY
NEET UG 2026

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम से ठीक पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और केंद्र सरकार के बीच विवाद कानूनी लड़ाई में बदल गया है। टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-टेस्ट परीक्षा से पहले भारत में प्लेटफॉर्म की पहुंच अस्थायी रूप से बैन कर दी गई थी। मामले का उल्लेख बुधवार को न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष किया गया, जिन्होंने इस पर आज ही सुनवाई के लिए सहमति जताई।

केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों को ठगी, फर्जी पेपर लीक और परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोहों से बचाने के लिए उठाया गया है। वहीं टेलीग्राम का तर्क है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना एक कठोर कदम है और इससे लाखों सामान्य यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं। 21 जून को होने वाली नीट यूजी री-टेस्ट परीक्षा पर देशभर के लाखों छात्रों की नजरें टिकी हैं। NTA ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी कथित लीक पेपर या सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें।

टेलीग्राम ने कोर्ट में क्या कहा?

टेलीग्राम ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना अनुपातहीन कदम है। कंपनी का कहना है कि यदि कुछ चैनल या समूह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन सभी यूजर्स को प्रभावित करना उचित नहीं है।

एडिट फीचर भी किया गया बंद

सरकार ने टेलीग्राम को भारत में पहले से पोस्ट किए गए संदेशों के एडिट फीचर को 30 जून तक निष्क्रिय करने का निर्देश भी दिया है। एजेंसियों का कहना है कि इस फीचर का इस्तेमाल बाद में संदेशों को बदलकर कथित पेपर लीक के फर्जी सबूत बनाने में किया जा रहा था।

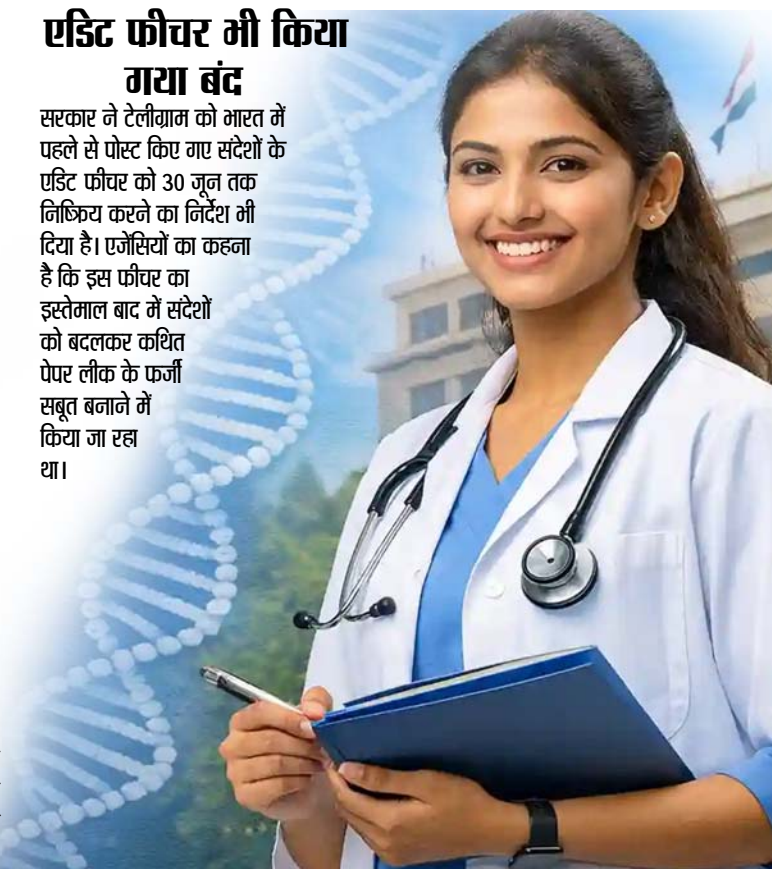

930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र

स्वराज इंडिया ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटर (ग्रेड-ए) अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचारमुक्त बनाया है। यही कारण है कि आज प्रदेश के लाखों युवाओं का सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं पर विश्वास मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में कंप्यूटर ऑपरेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

- मुख्यमंत्री बोले- पारदर्शी भर्ती से युवाओं का बढ़ा विश्वास
- कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती की जा रही है। उन्होंने नव नियुक्त कर्मियों से कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सराहना करते हुए इसे युवाओं के लिए भरोसे का नया आधार बताया।

लोक भवन सभागार में आयोजित यह कार्यक्रम प्रदेश सरकार की रोजगार सृजन और सुशासन की प्रतिबद्धता का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया।

सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम सख्त

तीन अधिकारियों का वेतन रोका गया, कई विभागों को नोटिस

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

रैंकिंग सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने दिखाई सख्ती, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड (विकास एवं राजस्व कार्य) तथा निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।बिना पूर्व अनुमति बैठक से अनुपस्थित रहने पर पर्यटन अधिकारी नीलम गौतम, पर्यटन विभाग की कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर सुखवीर सिंह तथा जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता संदेश सिंह तोमर के वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। वहीं जननी सुरक्षा योजना में लगातार तीन माह से 'डी' श्रेणी प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का आदेश दिया गया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिन विभागों की लापरवाही के कारण जनपद की रैंकिंग प्रभावित होगी, उनके जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

फैमिली आईडी योजना की समीक्षा में जनपद को 'सी' श्रेणी मिलने पर सभी खंड विकास अधिकारियों, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए।

आबकारी विभाग और मंडी शुल्क विभाग को लगातार 'डी' ग्रेड मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।

इसके अलावा 12 निर्माण परियोजनाओं को समयसीमा के भीतर पूरा न करने पर चिकित्सा शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, गृह एवं गोपन, कारागार, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम सहित कई विभागों के परियोजना अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं की समान जिम्मेदारी है।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उप जिलाधिकारी सदर अनुभव सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नेपाल से कानपुर लाई जा रही करोड़ों की चरस पकड़ी दो तस्कर गिरफ्तार

साउथ जोन पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई, आईपीएस सुमित रामटेके के नेतृत्व में बड़ी सफलता

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कमिश्नरेट पुलिस और क्राइम ब्रांच को नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। साउथ जोन के अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) आईपीएस सुमित रामटेके के नेतृत्व में बर्रा थाना क्षेत्र में देर रात की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान दो अंतरराज्यीय चरस तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने उनके कब्जे से करोड़ों रुपये मूल्य की चरस बरामद की है, जिसे नेपाल से कानपुर लाया जा रहा था।पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय थे और नेपाल से चरस की खेप लाकर कानपुर समेत आसपास के जिलों में उसकी आपूर्ति करते थे।

गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और बर्रा पुलिस ने संयुक्त रूप से घेराबंदी कर दोनों तस्करों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई।प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और सप्लाई चेन की जांच में जुट गई है। अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबार को बड़ा झटका लगा है।एडीसीपी सुमित रामटेके ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। विशेष रूप से युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ÷व्हाइट पाउडर÷ और अन्य मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।पुलिस की इस कार्रवाई को हाल के दिनों में नशा तस्करों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ी शिक्षकों की बेचैनी !

» यू पी सरकार करने जा रही है खत्म, होगी विभागीय टीईटी परीक्षा

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सालों से पढ़ा रहे लाखों शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब ऐसे शिक्षकों के लिए एक विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है जो बिना टीईटी पास किए लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में वर्तमान में करीब 1.86 लाख शिक्षक बिना टीईटी (टेट) पास किए बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक कड़े और ऐतिहासिक आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए महज एक हफ्ते के भीतर सभी जिलों से ऐसे नॉन-टीईटी शिक्षकों का पूरा ब्योरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बेहद अहम फैसले में साफ कर दिया है कि देश में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो सकता। कोर्ट ने वर्ष 2010 से पहले के नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। अदालत ने इन सेवारत शिक्षकों को राहत देते हुए परीक्षा पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक की समयसीमा तय की है। अगर इस अवधि के भीतर शिक्षकों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की तो उनकी नौकरी पर बड़ा संकट आ सकता है। इसी आदेश के अनुपालन में विभाग ने एक सप्ताह में सभी जिलों से डेटा मांग लिया है ताकि आगे की कार्ययोजना बनाई जा सके।

परमट घाट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कानपुर आगमन पर उन्होंने परमट मंदिर में पूजन एवं दर्शन किए और परमट घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया

स्वच्छता साथ में सांसद रमेश अवस्थी विधायक सुरेंद्र मैथानी भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल दिक्षित महामंत्री अभिनव दीक्षित एवं कार्यक्रम संयोजक अभिमन्यु सक्सेना समेत कई भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रूमा और जाजमऊ में केडीए का बड़ा बुलडोजर एक्शन

सरकारी 60 बीघा जमीन कब्जामुक्त, 85 बीघा अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने बुधवार को अवैध कब्जों और बिना स्वीकृति विकसित की जा रही प्लाटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए भूमाफियाओं पर करारा प्रहार किया। प्रवर्तन और भूमि बैंक की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए लगभग 60 बीघा भूमि को कब्जामुक्त कराया, जबकि 85 बीघा क्षेत्र में चल रही अवैध प्लाटिंग और निर्माण गतिविधियों पर नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

विशेष कार्याधिकारी एवं उपजिलाधिकारी डॉ. रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों में हड़कंप मच गया। केडीए की टीम ने रूमा, वाजिदपुर जाजमऊ और अहिरवां क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे और निर्माण ध्वस्त कर दिए।

केडीए की जमीन पर कब्जा करने वालों पर चला बुलडोजर

रूमा और वाजिदपुर जाजमऊ में प्राधिकरण की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त करते हुए करीब 18 बीघा भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। वहीं अहिरवां क्षेत्र में लगभग 41 बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर आंशिक ध्वस्तीकरण करते हुए बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण तोड़ दिए गए। केडीए अधिकारियों के अनुसार प्लाटिंगकर्ताओं और भूखंड खरीदारों द्वारा शमन मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया, जिसे जनभावनाओं के दृष्टिगत सशर्त मंजूरी दी गई है। यदि निर्धारित अवधि में मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया तो दोबारा बुलडोजर कार्रवाई होगी।

20 अवैध परियोजनाएं रडार पर

केडीए ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 20 अवैध प्लाटिंग, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए हैं। इनमें सबौली, फुफवार सुईथोक, सरसौल, हाथीपुर, परसौली समेत कई क्षेत्रों की अवैध प्लाटिंग शामिल हैं। इसके अलावा किदवई नगर, कृष्णा नगर और गांधीग्राम में बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित व्यावसायिक गतिविधियां भी जांच के दायरे में आ गई हैं।

ओएसडी डॉक्टर रवि प्रताप सिंह की कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप, 20 अवैध परियोजनाओं को नोटिस, 27 जून को फिर चलेगा बुलडोजर

27 जून को फिर गरजेगा बुलडोजर

केडीए ने चेतावनी दी है कि पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद संतोषजनक जवाब न देने वाले पांच बड़े अवैध प्रोजेक्टों पर 27 जून 2026 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इनमें स्टार लैंड डेवलपर्स, स्टार ग्रीन सिटी सहित कई अवैध प्लाटिंग परियोजनाएं शामिल हैं।

भूमाफियाओं को अंतिम चेतावनी

केडीए अधिकारियों ने साफ कहा है कि प्राधिकरण की अर्जित भूमि, ग्राम समाज की जमीन या सीलिंग भूमि पर कब्जा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डॉ रवि प्रताप सिंह ने जनता से की अपील

केडीए ने लोगों से अपील की है कि केवल स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही निर्माण कार्य कराएं तथा किसी भी प्लाट या संपत्ति की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की जांच अवश्य करें। ओएसडी का कहना है कि अवैध निर्माण और प्लाटिंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने भाजपा पदाधिकारियों संग की बैठक, संगठन और विकास कार्यों पर हुआ मंथन

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कानपुर सर्किट हाउस में भाजपा जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, जनसमस्याओं तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपमुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की समस्याओं, विकास योजनाओं की प्रगति तथा आमजन से जुड़े विषयों पर फीडबैक लिया। उन्होंने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया।

बैठक में भाजपा महानगर अध्यक्ष शिवराम सिंह एवं अनिल दीक्षित, जिलाध्यक्ष उपेन्द्र नाथ पासवान, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेन्द्र मैथानी, महेश त्रिवेदी, मोहित सोनकर सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों तथा संगठन की आगामी रणनीतियों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए लगातार कार्य कर रही है और विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है।

सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक को आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा पदाधिकारियों ने भी क्षेत्रीय विकास और जनहित के मुद्दों पर उपमुख्यमंत्री को सुझाव एवं मांगपत्र सौंपे।

डिजिटल सुरक्षा के लिए किया जागरूक

» स्वराज इंडिया संवाददाता

डीसीपी पश्चिम एस.एम. कासिम आबिदी ने कहा— जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम

कानपुर। अपराध मुक्त सामाजिक चिकित्सा समिति, सीआईएसएफ पनकी तथा पनकी तापीय विस्तार परियोजना के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को सीआईएसएफ लाइन, नई कॉलोनी पनकी में साइबर अपराध जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सचेत करना तथा सुरक्षित डिजिटल वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपायुक्त पश्चिम एसएम. कासिम आबिदी रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इनसे बचाव के लिए लोगों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक अथवा ओटीपी साझा करने से बचने की अपील की।विशिष्ट अतिथि पनकी तापीय विस्तार परियोजना के महाप्रबंधक विजय बहादुर तथा सीआईएसएफ पनकी के डिप्टी कमांडेंट अनुपम त्रिपाठी उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने डिजिटल सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए साइबर अपराधों से बचाव के लिए सतर्क रहने का संदेश दिया।शिविर में साइबर अपराध विशेषज्ञ उपनिरीक्षक शुभम यादव, मुख्य आरक्षी राजीव कुमार, आरक्षी रॉबिन सिंह, आरक्षी अभिषेक यादव, उपनिरीक्षक दुर्गेश शुक्ला एवं उपनिरीक्षक अफरोज अहमद ने ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया अपराध और साइबर सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम में अपराध मुक्त सामाजिक चिकित्सा समिति के चेयरमैन उत्तर प्रदेश आशुतोष बाजपेयी, महासचिव योगेश बाजपेयी, सचिव गोपाल गुप्ता सहित अनेक गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों एवं समिति के सदस्यों ने सहभागिता की। राजेश शुक्ला एवं दीपक अवस्थी की विशेष उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के अंत में समिति की ओर से सभी अतिथियों, विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। आयोजकों ने कहा कि जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज की आधारशिला हैं और साइबर अपराधों से बचाव के लिए सतत जागरूकता अभियान आवश्यक हैं।

डीपीआरओ साहब, सुंदरपुर में प्यासे हैं सरकारी हैंडपंप

» खराब हैंडपंपों से त्रस्त हैं ग्रामीण, गांव में बढ़ रहा है सबमर्सिबल बोरिंग का चलन

» स्वराज इंडिया संवाददाता

रसूलाबाद। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच रसूलाबाद विकासखंड क्षेत्र की मौजमपुर ग्राम पंचायत के मजरा सुंदरपुर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी समस्या के प्रति उदासीन बने हुए हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, गांव में पानी की टंकी से आपूर्ति होने पर ही पानी उपलब्ध हो पाता है। दोपहर और रात के समय जरूरत पड़ने पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। वहीं घरों में लगे नलों से खारा पानी आ रहा है और क्षेत्र में जलस्तर भी लगातार नीचे जा रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगे दो सरकारी हैंडपंप लंबे समय से खराब पड़े हैं। कागजों में हैंडपंप चालू दर्शाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में दोनों हैंडपंप रीबोर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव को समस्या से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं किया गया।

ग्रामीण शिव सिंह,रामलखन राजपूत,शिव सिंह,पुष्पेंद्र आदि और लोगों बताया कि यदि सरकारी हैंडपंपों को जल्द चालू करा दिया जाए तो उन्हें चौबीसों घंटे पेयजल उपलब्ध हो सकता है। वर्तमान में टंकी की आपूर्ति पर निर्भर रहने के कारण गांव में अक्सर पानी की किल्लत बनी रहती है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए भटकना पड़ रहा है।इस संबंध में ग्राम पंचायत सचिव दिग्विजय और एडीओ पंचायत जेपी शुक्ला से संपर्क करने का प्रयास दो बार किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से खराब हैंडपंपों की शीघ्र मरम्मत और स्थायी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

रूरा थाना बना दलालों का अड्डा?

» फरियादी बेहाल, अधिकारियों के आदेश के बाद भी नहीं दर्ज होती रिपोर्ट

» खनन और वसूली के मामले में बदनाम रह चुका है रूरा थाना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जनपद के रूरा थाना क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और पीड़ितों का आरोप है कि थाने में पुलिस से अधिक प्रभाव दलालों का है। थाने में आने वाले फरियादियों को न्याय दिलाने के बजाय कथित तौर पर दलालों के माध्यम से सौदेबाजी की जाती है और बिना उनकी मध्यस्थता के कोई काम आसानी से नहीं होता।

सूत्रों के अनुसार सुबह से देर रात तक थाने परिसर में कुछ कथित दलाल सक्रिय रहते हैं। पीड़ितों का आरोप है कि ये लोग स्वयं को पुलिस अधिकारियों का करीबी बताकर फरियादियों से संपर्क करते हैं और मामलों के निस्तारण के नाम पर सौदेबाजी करते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनकी बात नहीं मानता तो उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रूरा थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पूरे दिन थाने में सक्रिय रहने वाले बाहरी व्यक्तियों की वास्तविक भूमिका सामने आ सकती है। लोगों का आरोप है कि थाने की कार्यप्रणाली पर इन कथित दलालों का प्रभाव साफ दिखाई देता है।

वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई शिकायत

सिमरामऊ गांव निवासी रोहित कुशवाहा ने आरोप लगाया कि 24 मई को हुई घटना की सूचना देने के बावजूद उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही सूचना दर्ज की गई।इसी प्रकार 29 मई को एक जूनियर हाईस्कूल में हुई चोरी के मामले में प्रधानाध्यापक दीपक द्विवेदी द्वारा तहरीर देने और उच्चाधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया।

हत्या के प्रयास का आरोप, धाराएं बदलने की शिकायत

सादीपुर निवासी रोली मिश्रा ने आरोप लगाया कि 4 जून को शिवली-रूरा मार्ग पर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। पीड़िता का कहना है कि थाने पहुंचने पर उसकी तहरीर लेकर उसे वापस भेज दिया गया। बाद में चिकित्सीय परीक्षण और वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन आरोप है कि घटना की गंभीर धाराओं को कम कर रिपोर्ट दर्ज की गई।यदि यह आरोप सही हैं तो यह न केवल पीड़ितों के न्याय के अधिकार का हनन है, बल्कि पुलिस की निष्पक्षता और कार्यशैली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करता है।

सीसीटीवी जांच से खुल सकती है थाने की हकीकत

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि रूरा थाने के पिछले कई सप्ताह के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए तथा थाने में सक्रिय बाहरी व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल की जाए। लोगों का कहना है कि इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर थाने की व्यवस्था पर किसका नियंत्रण है।

मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक एवं उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा थाने में दलालों की कथित सक्रियता पर रोक लगाने की मांग की है, जिससे आम जनता को बिना किसी दबाव और बिचौलियों के न्याय मिल सके।

सम्पादकीय

पंचायतें बन रही हैं बदलाव की वाहक

हाल के दिनों में पंजाब के बाद, हिमाचल के लिए भी नशीले पदार्थों का तेजी से बढ़ता दुरुपयोग एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है। नशे के बढ़ते सेवन की जो समस्या कभी सीमावर्ती राज्यों व सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित मानी जाती थी, अब दुर्भाग्य से वह इस पहाड़ी राज्य के गांवों तक पहुंच गई है। जिससे कई परिवारों का अस्तित्व, लोगों की आजीविका और युवा पीढ़ी का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे हालात में राज्य सरकार का वह फैसला एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है, जिसमें नशीले पदार्थों से मुक्ति के अभियान 'चिट्टा-मुक्त गांव' में पंचायतों को शामिल करने का रणनीतिक निर्णय लिया गया है। सालों तक इस संकट को कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न माना जाता रहा है। नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने के लिये सप्लायरों व नशे की आदत का शिकार लोगों की गिरफ्तारी, नशीले पदार्थों की बरामदगी और पुलिस की कार्रवाई को प्राथमिकता बना लिया गया था। निस्संदेह, कानून के अनुपालन के बिना इस संकट का समाधान संभव भी नहीं था, लेकिन सिर्फ इन प्रयासों से सफलता कम ही मिली। नशीले पदार्थ बेचने वालों की गिरफ्तारी के बाद सप्लाई चेन तेजी से बदल जाती है। नशे के कारोबारी स्थानीय तंत्र की कमजोरी का लाभ उठाते और नये लोग नशे की लत की चपेट में आ जाते थे। इस संकट के बने रहने ने संकेत दिए कि यह समस्या सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि इसे एक सामाजिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े संकट के रूप में भी देखा जाना चाहिए। निर्विवाद रूप से किसी ग्रामीण समाज में पंचायतों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायतें ग्रामीण परिवेश में स्थानीय हालात को बेहतर ढंग से समझती हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें स्थानीय समुदायों का विश्वास भी हासिल होता है। वे गांव के लोगों के व्यवहार संबंधी बदलावों को आसानी से से पहचान सकती हैं। ऐसे बदलाव जिन्हें दूर बैठे प्रशासन व पुलिस के अधिकारी नहीं समझ सकते। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि यदि पंचायतों को प्रभावी अधिकार और संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो वे जागरूकता अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। साथ ही ग्रामीण परिवारों को समय रहते मदद लेने को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इतना ही नहीं, वे इस जागरूकता अभियान का दायरा बढ़ाने और बेहतर परिणाम हासिल करने के लिये स्कूल तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सार्थक तालमेल स्थापित कर सकती हैं। साथ ही बिना किसी भेदभाव के, संवेदनशील ढंग से पुनर्वास के प्रयासों में मदद कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर गांव स्तर पर निगरानी समितियां बनाकर पंचायतें नशे की आपूर्ति श्रृंखला पर नजर रख सकती हैं। वे समय रहते कानून के क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों को भी सतर्क करने में मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा बेहतर परिणाम हासिल करने के लिये पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और काम को बेहतर ढंग से करने के लिये जरूरी दिशा-निर्देश भी दिये जा सकते हैं।

यह भी हकीकत है कि पेशेवर अधिकारियों व कर्मचारियों की मदद के बिना गांवों की चुनी हुई संस्थाओं के द्वारा नशे की समस्या से पूरी तरह निपट पाना संभव नहीं है।

इसके अलावा नशे पर शिकंजा कसने के लिये जरूरी होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए। वहीं दूसरी ओर नशीले पदार्थों के सेवन के खतरे का सामना कर रहे युवाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने की भी जरूरत होगी।

अपने हक के लिए जीवटता का संघर्ष

निरंजन भंडारी

विनेश फोगाट का संघर्ष सफलता-असफलता, उम्मीद-निराशा के बीच झूलते हुए भी हथियार न डालने की मिसाल है। एक ऐसी महिला जो हालात, उम्मीदों और उन संस्थाओं से लगातार जूझ रही है जिनका मकसद उसे आगे बढ़ाना और सहारा देना था। हालात बेशक उनके पक्ष में नहीं, लेकिन उनमें कुश्ती की दुनिया के लिए संभावनाएं बाकी हैं।बैर निकालने पर उतारू दुनिया से मिले घावों को भरने को कृतसंकल्प चित्त असंभव को भी संभव कर सकता है। इकतीस साल की विनेश फोगाट एक ऐसी ही मिसाल हैं।

उनकी जिंदगी की कहानी किसी गल्प कहानीकार तक को यह सोचने पर मजबूर कर दे कि सफलता-असफलता, उम्मीद-निराशा के बीच झूलते हुए भी हथियार न डालने का क्या मतलब होता है। उनकी कहानी एक ऐसी महिला की है जो हालात, उम्मीदों, बदकिस्मती और उन संस्थाओं से लगातार जूझ रही है, जिनका काम उन्हें आगे बढ़ाना था।सालों के कड़े प्रशिक्षण, अपने भार-वर्ग में बने रहने के लिए वज़न पर लगातार अंकुश रखने की वजह से तराशा हुआ उनका चेहरा उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी का रूप प्रस्तुत करता है, जिसके अंदर अभी भी जीत की भूख है और जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जी-जान से दृढ़संकल्प है। यह चेहरा केंद्रित ध्यान, पक्के इरादे और चुनौतियों का सामना करने वाले का है। यह उनके मानस की झलक दिखाता है, और उनके शब्द : 'मैं इस कुश्ती के गद्दे पर वापस आऊंगी'- जो उन्होंने पिछले महीने अपनी वापसी वाला कुश्ती मुकाबला हारने के कुछ ही सेकंड बाद कहे थे, एक ऐसी आत्मा की अभिव्यक्ति, जो ज़ख्मी तो है लेकिन झुकी नहीं है।सोचिए, वापसी की अथक तैयारी करना, नवजात बच्चे को आंचल में भरकर रखने के जिंदगी के बेशकीमती पलों का मोह तजना, और फिर प्रतियोगिता की पूर्व-संध्या पर यह पता चलना कि आपको प्रतियोगिता में भाग लेने के अयोग्य करार दिया गया है। पेरिस ओलंपिक के उस दुखद दिन के लगभग दो साल बाद, जब मात्र 100 ग्राम ज़्यादा वज़न ने उन्हें स्वर्ण पदक जीतने के मौके से वंचित कर दिया था और प्रतियोगिता में उनके शानदार अभियान का दुखद अंत हुआ था, आखिरकार वह फिर से प्रतियोगिता के लिए तैयार थीं। जगह थी गोंडा, जोकि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक और कुश्ती का गढ़ है- वही व्यक्ति जिन पर विनेश और कई साथी पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।वहां मिला यह झटका अधिकांश एथलीटों के संकल्प को तोड़ने के लिए काफ़ी था। लेकिन विनेश के लिए नहीं। तीन कॉमनवेल्थ खेल स्वर्ण पदक, एक एशियन खेल स्वर्ण पदक, एक एशियन चैंपियनशिप स्वर्ण पदक और दो विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक जीतने वाली इस पहलवान का रिकॉर्ड, उन्हें अब तक की सबसे महान भारतीय महिला पहलवानों में से एक बनाता है। पेरिस का उनका सफ़र बहुत अच्छी तरह दर्ज है। यह साहस, त्याग और अटूट इच्छाशक्ति से भरा एक अभियान था, जो उन्हें ओलंपिक में कामयाबी के बहुत करीब ले गया। शरीर से न घट सके उस अतिरिक्त 100 ग्राम वज़न ने उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था। 'इंडियन एक्सप्रेस' में निहाल कोशी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा = 'उसके बाद तो मौत ही है, आगे कुआं... पीछे खाई' इंसाफ़ की उनकी पुकार और आवाज़ उठाने की हिम्मत ने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। वह एक राजनीतिक पार्टी में शामिल हुईं, विधानसभा चुनाव जीता, मां बनीं, फिर भी रेसलिंग मैट रूपी गोद और जड़ के बिना खुद को अनाथ महसूस किया। ताजिंदगी विनेश ने मुश्किलों का सामना किया, उन्हें ललकारा और ऐसी ताकत के साथ उन पर जीत हासिल की जो दुनिया में कम ही देखने को मिलती है। एक रूढ़िवादी, पुरुष-प्रधान समाज की बंदिशों, कम उम्र में पिता को खो देना, मां के कैंसर से संघर्ष से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचाइयां पाने तक के उनके सफ़र को देखिए। इसमें ताकतवर व्यवस्था के ख़िलाफ़ उनकी उस निडर आवाज़ को भी जोड़ दें, जो उनके खेल के भविष्य को तय कर सकती थी, तब उनके फौलादी इरादों की तारीफ़ किए बिना नहीं रहा जा सकता, जोकि उनका चारित्रिक गुण है।खेल में कामयाबी पाने के लिए शरीर को तकलीफ़ें सहने के काबिल बनाया जा सकता है, लेकिन बैर निकालने को तुले माहौल के दबाव के बीच मन को अडिग और मज़बूत बनाए रखना कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि ऐसा माहौल इंसान के इरादों को तोड़ देता है। ?वह बच्ची थीं, जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और उनकी मां को कैंसर से जूझना पड़ा। पेरिस ओलंपिक से पहले, अपने विरोध-प्रदर्शन के दौरान उन्होंने खुद कहा था = 'अगर एक अकेली महिला (उनकी मां), जो पढ़ी-लिखी नहीं थीं, अकेले समाज से लड़ सकती है और हमें बड़ा पहलवान बना सकती हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने पदक जीते, यह तो ठीक है, लेकिन अगर हम यह लड़ाई जीतते हैं, तो वह गर्व से कहेंगी, 'मैंने ही इन्हें जन्म दिया है'। तीन साल बाद, वह फिर से उसी विशेष विद्रोही तेवर के साथ लौटी हैं। अगर उनकी मां उनकी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हैं, तो उनका एक साल का बेटा उस काम को करने की हिम्मत दे रहा है, जिसे बहुत से लोग लगभग नामुमकिन मानते हैं।उनकी बात को फिर से दोहराते हुए 'जब मैं ओलंपिक्स से लौटी, तो मैं परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी।

अदालती फैसले के सामाजिक संकेतों को समझें

कोर्ट ने समाज को सोच बदलने को इशारा किया है।?घर की जीवन रेखा स्त्री का मूल्य उस दिन तय नहीं होना चाहिए जब उसकी कमी खले। वास्तव में उसका मूल्य को तभी से प्रतिष्ठा मिले, जब वह बिना पदनाम, वेतन और औपचारिक पहचान के घर को जीवंत करती हो।कुछ फैसले अदालतों के रिकॉर्ड में दर्ज होकर खत्म नहीं होते। वे समाज की सोच में प्रवेश करते हैं और उन मान्यताओं को चुनौती देते हैं जिन्हें लंबे समय से सामान्य मान लिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जिसमें सड़क दुर्घटना में एक गृहिणी की मृत्यु के मामले में घरेलू श्रम के आर्थिक मूल्य को स्वीकार किया गया

, ऐसा ही फैसला है। पहली नजर में यह मामला महज मुआवजे के निर्धारण का लग सकता है, लेकिन इसकी असली गूंज उससे कहीं आगे जाती है। यह उस सामाजिक सोच पर सवाल उठाता है, जिसने घर के भीतर होने वाले महिलाओं के श्रम को प्रतिष्ठा नहीं दी।अदालत ने माना कि गृहिणी सही मायने में 'होममेकर' है। उसका श्रम उत्पादक है, उसका योगदान वास्तविक है और उसकी अनुपस्थिति का असर केवल भावनात्मक नहीं, आर्थिक और संरचनात्मक भी होता है। सवाल यह नहीं है कि अदालत ने घरेलू श्रम का आर्थिक मूल्य किस आधार पर तय किया। प्रश्न यह है कि जिस श्रम पर करोड़ों परिवार टिके हुए हैं, उसे श्रम मानने में हमें इतना समय क्यों लगा।भारत में परिवार को एक संस्था के रूप में देखा गया है। उसकी स्थिरता, उसकी सामाजिक भूमिका और सांस्कृतिक महत्व पर लगातार बात होती रही है। लेकिन इस स्थिरता को बनाए रखने वाले श्रम पर उतनी गंभीर चर्चा नहीं हुई। घर चलाना केवल खाना बनाने तक सीमित नहीं होता। यह समय प्रबंधन, संसाधनों का संतुलन, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल, सामाजिक संबंधों का निर्वाह और परिवार की भावनात्मक संरचना को संभालने की निरंतर प्रक्रिया है। घर के भीतर होने वाला यह श्रम इसलिए अदृश्य हो जाता है क्योंकि वह बाजार के बाहर होता है। जिस काम के लिए बाहर किसी को नियुक्त किया जाए तो उसका भुगतान तय होता है, वही काम जब घर के भीतर किया जाता है तो उसे जिम्मेदारी, प्रेम या संस्कार का विस्तार मान लिया जाता है। यहां समाज को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। हमारे यहां लंबे समय तक एक सामान्य वाक्य चलता रहा, 'वह काम नहीं करती, घर संभालती है।' कथन के भीतर एक गहरी सामाजिक संरचना छिपी है।सम्मान और मूल्य एक चीज नहीं हैं। सम्मान भावनात्मक

हो सकता है, लेकिन मूल्य सामाजिक स्वीकृति का आधार बनता है। जिस योगदान को मूल्य नहीं मिलता, धीरे-धीरे उसकी भूमिका को स्वाभाविक मान लिया जाता है। फिर उसके पीछे का श्रम, समय और कौशल दिखाई देना बंद हो जाता है। विडंबना यह है कि परिवार की पूरी व्यवस्था को संभालने वाला व्यक्ति अक्सर आर्थिक परिभाषाओं में 'निर्भर' माना जाता रहा। यह विरोधाभास सोच का भी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी सोच को चुनौती देता है। निस्संदेह, अदालत के फैसले ने नुकसान की परिभाषा को नया अर्थ दिया।अब तक जब किसी नौकरीपेशा व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसकी आय को परिवार की आर्थिक क्षति का आधार माना जाता था। लेकिन गृहिणी की मृत्यु के मामलों में यह तर्क दिया जाता रहा है कि उसकी प्रत्यक्ष आय नहीं थी, इसलिए आर्थिक नुकसान सीमित माना जाता है। वास्तव में किसी होममेकर की अनुपस्थिति केवल एक सदस्य की अनुपस्थिति नहीं होती। उसके साथ घर की पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। बच्चों की दिनचर्या बदलती है, देखभाल की प्रणाली बदलती है, घरेलू खर्च का स्वरूप बदलता है और परिवार की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है।यह फैसला बताता है कि हर वह काम जो वेतन में नहीं बदलता, वह मूल्यहीन नहीं होता। हालांकि, इस फैसले को महिलाओं के लिए वेतन की बहस तक सीमित करना भी उचित नहीं होगा। आज जब अर्थव्यवस्था, उत्पादकता और कार्यबल भागीदारी जैसे विषय चर्चा में हैं, तब यह स्वीकार करना जरूरी है कि सामाजिक पुनरुत्पादन, यानी परिवार का निर्माण और संचालन भी किसी अर्थव्यवस्था की बुनियादी शर्त है।घर मनुष्य निर्माण की पहली संस्था होता है। यदि उस संस्था को चलाने वाले श्रम को लगातार अदृश्य रखा जाएगा तो बराबरी और सम्मान पर आधारित समाज की कल्पना अधूरी रहेगी। यह फैसला समाज को संबोधित करता है कि क्या हम अपने घरों में श्रम की बराबरी को समझते हैं?

इन प्रश्नों के उत्तर अदालत नहीं दे सकती।

समाज को खुद तय करना होगा कि वह इस फैसले को केवल मुआवजे के मामले का निर्णय मानता है

या अपने समय के एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत की तरह पढ़ता है।

क्योंकि किसी होममेकर का मूल्य उस दिन तय नहीं होना चाहिए जब उसकी अनुपस्थिति दर्ज की जाए।

उसका मूल्य उस दिन पहचाना जाना चाहिए जब वह हर दिन बिना किसी पदनाम, वेतन और औपचारिक पहचान के घर को चलाने के लिए उपस्थित होती है।किसी समाज की परिपक्वता इस बात से नहीं मापी जाती कि वह श्रम का कितना भुगतान करता है।

यह फैसला उन महिलाओं के लिए सामाजिक स्वीकृति है, जिनकी उपस्थिति से घर केवल चलता नहीं बल्कि आकार लेता है। और शायद इसकी सबसे बड़ी शक्ति भी यही है। अदालत ने अपने हिस्से का निर्णय दे दिया है। अब समाज को अपने हिस्से का उत्तर देना है।

रजिस्ट्री कार्यालयों के निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं की हुंकार

राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा, फैसला वापस न लेने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन (रजिस्ट्री) कार्यालयों के प्रस्तावित विकेंद्रीकरण और निजीकरण के विरोध में मंगलवार को बिल्हौर तहसील में अधिवक्ताओं का आक्रोश खुलकर सामने आया। तहसील के तीनों अधिवक्ता संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम मनीष कुमार को सौंपा और प्रस्तावित व्यवस्था को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई। तहसील परिसर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। बार एसोसिएशन अध्यक्ष बृजेश कटियार, लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष जनार्दन यादव और एकीकृत बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनीत गुप्ता के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में तहसील स्तर पर रजिस्ट्री कार्य सुचारु रूप से संचालित हो रहे हैं, इसलिए निजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिवक्ताओं का कहना था कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को निजी हाथों में सौंपने से इसकी गोपनीयता और विश्वसनीयता प्रभावित होगी। साथ ही फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और दलालों की सक्रियता बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे भू-माफियाओं और दबंगों को भी बढ़ावा मिल सकता है, जिसका खामियाजा आम नागरिकों और किसानों को भुगतना पड़ेगा।

ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर अधिवक्ता, स्टाम्प विक्रेता, लेखपत्र लेखक और टंकक समेत हजारों लोगों के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं आम जनता को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है।

अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने प्रस्तावित योजना वापस नहीं ली तो प्रदेशव्यापी आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

रोजगार और पारदर्शिता पर जताई चिंता

अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि निबंधन कार्यालयों के निजीकरण से न केवल पारदर्शिता प्रभावित होगी बल्कि रजिस्ट्री कार्य से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका भी संकट में पड़ सकती है। उनका कहना था कि निजी एजेंसियों के हस्तक्षेप से आम नागरिकों को अधिक शुल्क चुकाना पड़ सकता है और विवादों की संख्या बढ़ सकती है।

कर्बला के शहीदों की याद में सजी मजलिस गूंजा या हुसैन

स्वराज इंडिया ब्यूरो

- मौलाना अज़ीम रिज़वी बोले– हक और इंसाफ का साथ देने वाला ही सच्चा हुसैनी
- अंजुमन-ए-जाफरिया ने की नोहाखानी व सीना-जनी

बिल्हौर(कानपुर)। मकनपुर – इलियासपुर स्थित शिफाहत इमाम बारगाह में कर्बला के शहीदों की याद में मजलिस का आयोजन किया गया। इस दौरान या हुसैन-या हुसैन की सदाओं से महफ़िल गूंज उठी। मजलिस में दूर-दराज से आए शायरों और उलमाओं ने शिरकत कर शहीदाने कर्बला को खिराज-ए-अकीदत पेश की। शायर शोएब गाजी, फ़राज़ जाफरी, सय्यद सज्जाद हुसैन और मुनफुल जाफरी ने अपने कलाम पेश किए, जिन्हें अकीदतमंदों ने खूब सराहा।

मुख्य वक्ता मौलाना सय्यद अज़ीम रिज़वी (आंबेडकर नगर) ने अपने खिताब में कहा कि हुसैनी वही है जो हक और इंसाफ का साथ दे तथा मजलूमों की मदद करे। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने इंसानियत और सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। मजलिस के दौरान अंजुमन-ए-जाफरिया ने नोहाखानी की तथा अकीदतमंदों ने सीना-जनी किया।

अंत में इशरत हुसैन ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ कराई। इस अवसर पर शहीद हसनैन, अरफात जाफरी, शानू रिज़वी, हाशम अब्बास, ज़ैनुल हयात, मुश्ताक रिज़वी, मशकूर ज़ैदी, मैकश रिज़वी, काशिफ रिज़वी समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे।

पारिवारिक विवाद में युवक और पत्नी पर हमला, जांच में जुटी पुलिस

स्वराज इंडिया ब्यूरो

- दासा निवादा गांव की घटना, शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

शिवराजपुर (कानपुर)। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के दासा निवादा गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान एक युवक और उसकी पत्नी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में युवक घायल हो गया, जबकि बीच-बचाव करने पहुंची उसकी पत्नी को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। दासा निवादा निवासी नेकचंद की पत्नी आरती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सोमवार सुबह पारिवारिक कहासुनी के दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि उनके ससुर और दो देवरों ने नेकचंद के साथ मारपीट कर दी। पति को बचाने पहुंची आरती के साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। मारपीट में घायल दंपती को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल शुरू की।

थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण जारी महिला ने एसडीएम से लगाई गुहार

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर(कानपुर)। तहसील क्षेत्र के चन्दपुरा गांव की एक महिला ने न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद उसकी भूमि पर निर्माण कार्य कराए जाने का आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी बिल्हौर से कार्रवाई की मांग की है।

ग्राम चन्दपुरा निवासी केशकुमारी पत्नी मुंशीलाल ने एसडीएम को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी आराजी संख्या 1114 एवं 1115 की भूमि को लेकर विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में ग्राम न्यायालय बिल्हौर में वाद लंबित है, जिसमें न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आरोप है कि गांव की ही सोनी पत्नी मनीष द्वारा अपनी भूमि के बजाय विवादित भूमि पर जबरन मकान का निर्माण कराया जा रहा है। न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी है, जिससे आदेश की अवहेलना हो रही है। पीड़िता ने प्रशासन से निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने तथा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले को लेकर राजस्व एवं प्रशासनिक स्तर पर जांच कराए जाने की चर्चा है।

दुश्मनी में रातोंरात काट डाली तैयार केले की फसल, किसानों को लाखों का नुकसान

» पीड़ित परिवारों का रो- रोकर का बुरा हाल

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

लखीमपुर खीरी। निघासन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मिर्जागंज में अज्ञात शरारती तत्वों ने दो किसानों की तैयार खड़ी केले की फसल काटकर बर्बाद कर दी। घटना से किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। वर्षों की मेहनत पर पानी फिर जाने से पीड़ित किसान सदमे में हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार मिर्जागंज निवासी घुरई ने लगभग एक बीघा तथा गुड्डू उर्फ अफसर अली ने करीब एक एकड़ क्षेत्र में केले की खेती की थी।

दोनों किसानों की फसल तैयार होकर बिक्री के अंतिम चरण में थी। आरोप है कि सोमवार रात अज्ञात लोगों ने खेतों में घुसकर बड़ी संख्या में केले के पौधों को काट दिया, जिससे पूरी फसल नष्ट हो गई।

मंगलवार सुबह जब किसान खेत पर पहुंचे तो वहां कटे पड़े केले के पौधों को देखकर उनके होश उड़ गए।

तैयार फसल को इस तरह बर्बाद देख दोनों किसान भावुक हो उठे। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई और घटना पर रोष व्यक्त किया।

पीड़ित किसानों का कहना है कि यह घटना किसी सुनियोजित शरारत या पुरानी रंजिश का परिणाम हो सकती है। किसानों ने निघासन पुलिस को तहरीर देकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों ने बताया कि खेती ही इन परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत है।

ऐसे में लाखों रुपये की फसल नष्ट होने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से किसानों को आर्थिक सहायता दिलाने तथा दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों का खेती से विश्वास उठ जाएगा।

सो रहा था थाना, निरीक्षण पर निकले कप्तान, 19 महिला पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज

निरीक्षण में महिला थाना परिसर में अधिकांश स्टाफ अनुपस्थित मिला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

मेरठ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने महिला थाना का औचक निरीक्षण कर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया। सुबह के समय किए गए इस निरीक्षण में थाना परिसर में अधिकांश स्टाफ अनुपस्थित मिला। जानकारी के अनुसार मौके पर केवल एक महिला पुलिसकर्मी मौजूद थी, जो विश्राम करती हुई पाई गई।निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना अभिलेखों और क्राइम रजिस्टर की जांच की तथा बिना किसी पूर्व सूचना के वहां से लौट गए। बाद में कार्यालय में संबंधित अभिलेख तलब किए जाने पर थाना स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच में स्पष्ट हुआ कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं निरीक्षण कर चुके थे।प्रकरण को गंभीर लापरवाही मानते हुए विभागीय कार्रवाई की गई। सूत्रों के अनुसार महिला थाना में तैनात 19 महिला पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में अनुशासन और कार्यप्रणाली को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था से जुड़े संस्थानों में ड्यूटी के प्रति लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। औचक निरीक्षणों का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाना है।

पूर्व सांसद बृजभूषण और विधायक प्रतीक भूषण को मिली जान से मारने की धमकी

राजस्थान कनेक्शन आया सामने

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

गोंडा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और उनके विधायक पुत्र प्रतीक भूषण सिंह को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक प्रतीक भूषण सिंह के निजी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात युवक ने फोन कर उन्हें और उनके पिता को हत्या की धमकी दी। मामले की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सदर विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह की तरफ से नगर कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 14 जून को क्षेत्र भ्रमण के दौरान दोपहर करीब 2.22 बजे विधायक के मोबाइल पर एक कॉल आई। फोन उठाते ही दूसरी ओर से युवक ने कहा, तुम्हें और तुम्हारे पिता दोनों को जान से मारने का इंतजाम

हो चुका है। खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। करीब 35 सेकेंड तक चली बातचीत के बाद कॉल काट दी गई।धमकी मिलने के बाद विधायक ने तत्काल पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की तकनीकी टीम को जांच में लगाया गया। विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह की तहरीर पर नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तहरीर में कहा गया है कि विधायक और उनका परिवार पूर्व से विभिन्न आपराधिक गिरोहों एवं असामाजिक तत्वों के निशाने पर रहा है। ऐसे में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि और उनके परिवार को मिली यह धमकी गंभीर सुरक्षा चुनौती है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी गई, वह राजस्थान के अलवर जिले के मांडावार क्षेत्र निवासी संदीप शर्मा पुत्र दयाराम शर्मा के नाम पर पंजीकृत है। पुलिस आरोपी तक पहुंचने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद ही धमकी देने के पीछे की वास्तविक वजह और मंशा स्पष्ट हो सकेगी

ऑटो चालक से मारपीट जातिसूचक गालियां देने का आरोप

» पीड़ित ने रुपए छीनने का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक के साथ मारपीट और जातिसूचक गालियां देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उससे नकदी भी छीन ली।

घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है।राजपुर थाना क्षेत्र के बुढ़ना गांव निवासी ऑटो चालक विनोद बाबू पुत्र रमेश चंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह राजपुर से अपने गांव लौट रहा था।

आरोप है कि भाल गांव के बाहर गांव के ही एक युवक ने अपने पांच साथियों के साथ मिलकर उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी।

पीड़ित के अनुसार, आरोपितों ने उसके साथ जातिसूचक गालियां दीं और गाना बजाकर निकलने को लेकर आपत्ति जताई।

मारपीट में उसे गंभीर चोटें आई हैं। विनोद बाबू का आरोप है कि हमलावरों ने उसकी जेब में रखे रुपए भी छीन लिए। उन्होंने बताया कि घटना की लिखित शिकायत थाने में दी गई है, लेकिन अभी तक उनका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया है।

वहीं, प्रभारी राजपुर थाना गुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से मारपीट और रुपए छीनने के आरोप लगाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में दोनों पक्षों के नशे में होने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बड़े मंगल पर तहसील सदर परिसर में विशाल भंडारा, हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। ज्येष्ठ माह के पावन बड़े मंगल के अवसर पर तहसील सदर परिसर, अकबरपुर में विशाल प्रसाद वितरण (भंडारा) का आयोजन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया गया। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण किया और पुण्य लाभ अर्जित किया।

भंडारे में श्रद्धालुओं को आम का जूस, पानी के बताशे तथा पारंपरिक पूआ प्रसाद वितरित किया गया। पूरे तहसील परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी राजकुमार पाण्डेय, तहसीलदार पवन कुमार, नायब तहसीलदार रविन्द्र नाथ मिश्रा तथा नायब तहसीलदार विक्रम पासवान सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राजस्व विभाग के कर्मचारियों और लेखपालों ने भी आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई।

अधिवक्ता समिति अकबरपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उल्लेखनीय सहभागिता रही। अधिवक्ताओं ने श्रद्धालुओं की सेवा और प्रसाद वितरण व्यवस्था में सहयोग किया। आयोजन में सामाजिक समरसता और जनसेवा की भावना का संदेश भी देखने को मिला।

अधिवक्ता समिति अकबरपुर के अध्यक्ष बिपिन चन्द्र दीक्षित ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग और हनुमान जी की कृपा से आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

भीषण गर्मी के चलते परिषदीय स्कूलों के संचालन समय में बदलाव की मांग तेज

» सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही स्कूल खोलने की शिक्षक संगठनों ने रखी मांग, नन्हे-मुन्ने बच्चों के स्वास्थ्य का दिया हवाला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच परिषदीय विद्यालयों के संचालन समय में बदलाव की मांग जोर पकड़ने लगी है। शिक्षक संगठनों और अभिभावकों का कहना है कि मौजूदा मौसम को देखते हुए विद्यालयों का संचालन सुबह के समय किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को लू और अत्यधिक गर्मी से बचाया जा सके।

उत्तर प्रदेशीय अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एल.बी. सिंह ने कहा कि जहां माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, वहीं बेसिक विद्यालयों में अध्ययनरत छोटे बच्चों को भीषण गर्मी के बीच विद्यालय आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किए जाने की मांग की।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाएं और लू का प्रकोप छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। ऐसे में विद्यालयों का संचालन सुबह के अपेक्षाकृत ठंडे समय में करना अधिक उपयुक्त रहेगा।

अन्य शिक्षक संगठनों का भी मानना है कि समय परिवर्तन से न केवल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी, बल्कि उनकी उपस्थिति और पढ़ाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भीषण गर्मी के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हिचक रहे हैं।

अभिभावकों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि वर्तमान मौसम को देखते हुए बच्चों को राहत मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि जब आधुनिक सुविधाओं से लैस निजी विद्यालयों में भीषण गर्मी के चलते अवकाश घोषित किया जा रहा है, तो बुनियादी सुविधाओं से वंचित सरकारी विद्यालयों को नियमित समय पर संचालित करने का औचित्य समझ से परे है।

ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश विद्यालयों में आज भी बिजली, पंखे, शुद्ध पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कई स्कूलों में बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसे में तेज गर्मी के बीच विद्यालय संचालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

शिक्षकों का कहना है कि अत्यधिक तापमान में विद्यालय संचालन बच्चों और शिक्षकों, दोनों के लिए कठिनाइयां बढ़ा सकता है। उनका मानना है कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब तक तापमान सामान्य नहीं हो जाता, तब तक विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन एक व्यावहारिक और छात्रहितैषी कदम साबित हो सकता है।

भोगनीपुर क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में महिला समेत तीन घायल मेडिकल कॉलेज रेफर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाएं और एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के बिल्हापुर गांव निवासी छोटी बिट्टी (50) पत्नी चंद्रपाल घर में चूल्हे पर खाना बना रही थीं। अचानक उनके कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात डॉ. राजवीर सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज अकबरपुर रेफर कर दिया। महिला की ननद रेखा देवी ने घटना की जानकारी दी।वहीं, दौलतपुर गांव निवासी संगीता पत्नी अनिल कुमार ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखरायां में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।इसी क्रम में सिखमापुर गांव के समीप सड़क हादसे में 11 वर्षीय किशोर लक्ष्य घायल हो गया। सिखमापुर निवासी कुलदीप ने बताया कि उनका पुत्र घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। घायल किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखरायां में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।तीनों मामलों में चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए घायलों को उच्च केंद्र भेजा है।

विधानसभा चुनाव की आहट के साथ बढ़ी सियासी सरगर्मी

टिकट के लिए दावेदारों ने झोंकी ताकत

रोचक होगा रसूलाबाद विधानसभा का रण, रणबांकुरे तैयार, भाजपा हैट्रिक तो सपा अपनी वापसी को बेताब

मो.मशरूफ नवाज़, स्वराज इंडिया

रसूलाबाद (कानपुर देहात)। उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बावजूद विभिन्न दलों के संभावित दावेदार क्षेत्र में सक्रिय होकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गए हैं। राजनीतिक गलियारों में चुनावी चर्चाएं तेज हैं और संभावित उम्मीदवार गांव-गांव तथा गली-गली पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस संभावना को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और सियासी समीकरण साधने में जुट गए हैं। वर्ष 2012 में अस्तित्व में आई रसूलाबाद विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास काफी रोचक रहा है। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस सीट पर प्रदेश स्तर के नेताओं की भी विशेष नजर रहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहली बार कन्नौज से सांसद बने थे। उनके बाद उनकी पत्नी डिंपल यादव ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वर्तमान में पुनः अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं।

रसूलाबाद विधानसभा सीट पर वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि उसके बाद लगातार दो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार भाजपा में टिकट के लिए एक दर्जन से अधिक नेता सक्रिय बताए जा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में भी कई दावेदार अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं।

पिछले तीन विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने हर बार अपना प्रत्याशी बदला, जिसमें उसे केवल एक बार शिवकुमार बेरिया के रूप में सफलता मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्येक चुनाव में नया चेहरा उतारा और महिला प्रत्याशियों पर भरोसा जताया, जिसके परिणाम स्वरूप दो बार सीट उसके खाते में गई। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो लगातार हर चुनाव में बसपा का वोट बैंक घटता चला आया। इसी प्रकार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भी सबसे खराब रहा। जिसको लेकर लड़ाई सपा और भाजपा में कांटे की देखने को मिल सकती है। संभावित चुनावी वर्ष नजदीक आते ही क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। संभावित प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पुराने और अनुभवी चेहरे पर दांव लगा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी जीत लिए टिकट के मामले में चौंका सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रमुख राजनीतिक दल किस उम्मीदवार पर अपना भरोसा जताते हैं और आगामी चुनाव में किसके सिर जीत का सेहरा बंधता है।

मोहर्रम की पहली तारीख पर राहगीरों को शरबत वितरण किया

» हजरत इमाम हुसैन र.अ. की याद में आयोजित हुआ सेवा कार्यक्रम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रसूलाबाद। पवित्र मोहर्रम माह के आगमन के साथ इस्लामी नववर्ष की शुरुआत हो गई है। मोहर्रम की पहली तारीख के अवसर पर कस्बा रसूलाबाद के विकास नगर, झींझक रोड पर हजरत इमाम हुसैन र.अ. की याद में स्थानीय लोगों द्वारा शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच आयोजित इस सेवा कार्य में राहगीरों को ठंडा शरबत पिलाकर राहत पहुंचाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने शरबत ग्रहण कर गर्मी से राहत महसूस की और आयोजन की सराहना की।आयोजकों ने बताया कि मोहर्रम का महीना त्याग, बलिदान, मानवता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। इसी भावना के तहत लोगों की सेवा के उद्देश्य से शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नफीस अली, नसीम अहमद, कमरुद्दीन, हसन अली, रिजवान मंसूरी, नन्हे पांडेय, पवन पांडेय, फरमान, अल्तमश, राशिद, अरमान अली, तौसीफ, सान्याल, ताज आलम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

24 जून तक बंद रहेंगे परिषदीय स्कूल, 25 जून से शुरू होगी पढ़ाई

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश सरकार ने भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ा दी है। शासन की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि 25 जून से नियमित पठन-पाठन शुरू होगा। यह नई व्यवस्था वर्ष 2026 से प्रभावी कर दी गई है।अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इससे पहले परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक निर्धारित था। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के कारण जिलाधिकारी स्तर पर अवकाश बढ़ाना पड़ता था। शासन के निर्देशानुसार 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे। इन तीन दिनों के दौरान लेसन प्लान तैयार करना, मिड-डे मील की व्यवस्था सुनिश्चित करना, पाठ्य पुस्तकों के वितरण की तैयारी, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आयोजित करना, बाल वाटिका की तैयारी, विद्यालय परिसर, रसोईघर और शौचालयों की साफ-सफाई, खेल सामग्री की उपलब्धता, स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब को क्रियाशील रखना तथा बिजली एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने जैसे कार्य पूरे किए जाएंगे।इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं द्वारा सामूहिक योगाभ्यास भी कराया जाएगा।शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निर्धारित शैक्षिक सत्र के अनुसार वर्ष में कम से कम 220 दिन पठन-पाठन अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही जिलाधिकारियों को स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पहले इस विधिक प्रावधान का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मुखर्जी नगर में ट्रांसफार्मर फुंका, 40 घरों की बिजली आपूर्ति ठप

भीषण गर्मी से लोग बिलबिलाए

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। राजपुर कस्बे के मुखर्जी नगर में 63 केवीए का ट्रांसफार्मर फुंक जाने से लगभग 40 घरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

ट्रांसफार्मर फुंकने के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से इसे बदला नहीं गया है। भीषण गर्मी और उमस के बीच छोटे बच्चों,

बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय निवासियों अनुपम तिवारी, गोपाल मिश्रा, रामू कटियार, दीपक मिश्रा, दीपू वर्मा, वीरेंद्र अवस्थी और हर्ष शुक्ला ने बताया कि

मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे से बिजली आपूर्ति बाधित है। बिजली न होने से पेयजल संकट के साथ-साथ लोगों के दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को दे दी गई थी। इसके बावजूद बुधवार दोपहर 12ः41

बजे तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका, जिससे लोगों में विभाग के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

इस संबंध में अवर अभियंता राहुल साहू ने

बताया कि खराब ट्रांसफार्मर को जल्द ही बदलवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

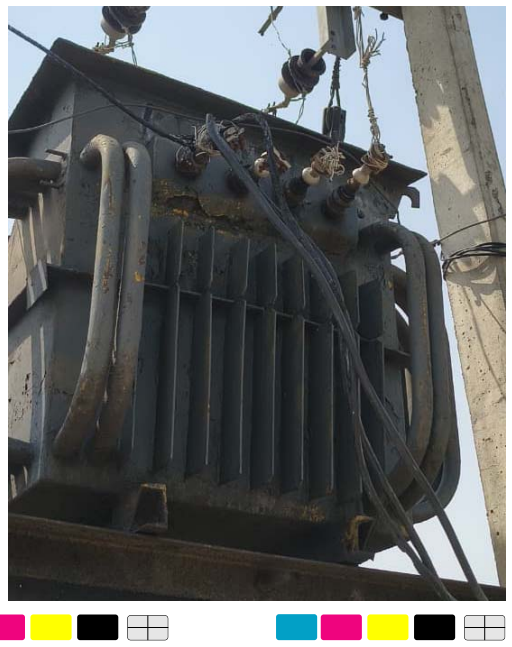

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच की मांग, कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण के अध्यक्ष संदीप शुक्ला एडवोकेट ने ज्ञापन दिया

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए सोने-चांदी और अन्य बहुमूल्य सामग्री की कथित चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण के अध्यक्ष संदीप शुक्ला एडवोकेट ने किया।

ज्ञापन में कहा गया है कि देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण और चढ़ावे से संबंधित बहुमूल्य धातुओं एवं शिलाओं की कथित चोरी का मामला अत्यंत गंभीर है और इसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले में अब तक प्रभावी कार्रवाई न होने से लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं।कांग्रेस पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति से मांग की कि प्रकरण में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई जाए तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जांच समिति गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ज्ञापन में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।

संदीप शुक्ला ने कहा कि धार्मिक स्थलों और उनसे जुड़ी आस्था की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की पारदर्शी जांच से श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत होगा और यदि कोई दोषी है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति कार्यालय और प्रशासन इस संवेदनशील मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

अयोध्या में होगा भव्य मॉडलिंग शो

5 अगस्त को ताज होटल में सजेगा ग्रैंड फिनाले

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में पहली बार बड़े स्तर पर फैशन और मॉडलिंग का मंच सजने जा रहा है। शहर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में ÷पहनावा बाय पारुल÷ की ओर से मॉडलिंग शो की घोषणा की गई। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता का ऑडिशन 25 जुलाई से शुरू होगा, जबकि ग्रैंड फिनाले 5 अगस्त को इलाहाबाद रोड स्थित ताज होटल में आयोजित किया जाएगा।

कार्यक्रम की एंकरिंग सुनैना करेंगी। आयोजन में शुयश सिंह को-फाउंडर की भूमिका निभाएंगे, जबकि कृष बौद्ध डायरेक्टर, अनुष्का गुप्ता मैनेजर तथा अन्नय तिवारी और खुशी तिवारी आयोजन से जुड़ी प्रमुख जिम्मेदारियां संभालेंगे।

आयोजकों के अनुसार ऑडिशन नाका स्थित सिल्वर स्पून फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी मॉडल हिस्सा लेंगे। रनवे-पेजेंट प्रतियोगिता की प्रवेश शुल्क 2000 रुपये निर्धारित की गई है।

आयोजकों ने बताया कि दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा।उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य अयोध्या की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराना तथा फैशन, मॉडलिंग और व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में युवाओं को नए अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम को लेकर युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है।

टोल प्लाजा विवाद: लूट, मारपीट या फिर राजनीतिक साजिश?

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

» निषाद पार्टी नेता करुणाकर पांडे पर एफआईआर परिवार ने आरोपों को बताया झूठा और प्रायोजित

अयोध्या। पूराकलंदर थाना क्षेत्र स्थित भरतकुंड टोल प्लाजा पर हुई एक घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। निषाद पार्टी के नेता एवं बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय माने जाने वाले करुणाकर पांडे उर्फ बब्बू के खिलाफ मारपीट, धमकी और रुपये छीनने जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं उनके परिवार ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार देते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार टोल प्लाजा के सुपरवाइजर उत्कर्ष सिंह ने आरोप लगाया है कि 16 जून की सुबह करुणाकर पांडे अपने साथियों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे और टोल शुल्क मांगने पर विवाद शुरू हो गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और जेब में रखे 7 हजार रुपये निकाल लिए गए।दूसरी ओर करुणाकर पांडे के भाई एवं अधिवक्ता अरुणाकर पांडे का कहना है कि घटना पूरी तरह मनगढ़ंत है। उनके अनुसार टोल प्लाजा पर पहले उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी और सूचना मिलने पर करुणाकर केवल हालात की जानकारी लेने पहुंचे थे। उनका दावा है कि न कोई मारपीट हुई और न ही किसी प्रकार की लूटपाट।

परिवार का आरोप है कि करुणाकर पांडे की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता से परेशान विरोधियों ने उनकी छवि धूमिल करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अब पूरे मामले की सच्चाई पुलिस विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही सामने आएगी।

प्रेमी के इंकार से आहत युवती ने उठाया खौफनाक कदम

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। बीकापुर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है। पुराकलंदर थाना क्षेत्र के हरिवंश चांदपुर गांव निवासी 20 वर्षीय शिवानी चौहान ने कथित रूप से प्रेमी द्वारा संबंध से इनकार किए जाने के बाद गला काटकर आत्महत्या का प्रयास कर लिया। गंभीर हालत में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

बताया जाता है कि शिवानी का सुरासराय निवासी करण चौहान से कई वर्षों से प्रेम संबंध था। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि दोनों पिछले करीब पांच माह से साथ रह रहे थे। परिजनों के विरोध के बाद युवक ने कथित तौर पर युवती को अपनाने और पहचानने से इनकार कर दिया।

मंगलवार को शिवानी अपनी मां और बहन के साथ युवक के घर पहुंची थी। आरोप है कि वहां युवक और उसके परिजनों ने किसी भी प्रकार के संबंध से इंकार कर दिया। इससे आहत होकर युवती ने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से जानकारी जुटाई जा रही है। युवती का उपचार जारी है।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण

दूसरे दिन भी एसआईटी की मैराथन जांच, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ

दान गिनती से लेकर संदिग्धों तक हर कड़ी खंगाली जा रही, करोड़ों के हार और चरण पादुका को लेकर भी नए सवाल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्याधाम। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरफेर की जांच कर रही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दूसरे दिन भी मंदिर परिसर में सात घंटे से अधिक समय तक गहन पड़ताल की। सूत्रों के अनुसार अब तक ट्रस्ट पदाधिकारियों, पुजारियों, बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों समेत 100 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच के केंद्र में दान प्राप्त करने, उसकी गिनती, अभिलेखीकरण और बैंक में जमा कराने की पूरी प्रक्रिया है।

मंगलवार को मंडलायुक्त लखनऊ विजय विश्वास पंत, आईजी किरण एस. और विशेष सचिव वित्त नील रतन की टीम ने ट्रस्ट कार्यालय में कई दौर की पूछताछ की।

सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान 40 से 50 ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है।

हार और चरण पादुका का मामला भी चर्चा में

इसी बीच एक नया दावा भी सामने आया है। आचार्य विनोद मिश्र ने आरोप लगाया है कि उनके शिष्य अजय विश्वकर्मा द्वारा भेंट किया गया करोड़ों रुपये मूल्य का हार और चरण पादुका आज तक सार्वजनिक रूप से मंदिर में प्रदर्शित नहीं हुई।

उनका दावा है कि यह चढ़ावा तत्कालीन कर्मचारी टिन्नू यादव ने प्राप्त किया था और उसकी रसीद भी जारी हुई थी। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही जांच एजेंसियों ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी की है।

सीसीटीवी फुटेज भी जांच के दायरे में

सूत्रों के अनुसार एसआईटी सीसीटीवी फुटेज, दान अभिलेखों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।

पूर्व में आठ माह के

सीसीटीवी रिकॉर्ड गायब होने के आरोप भी चर्चा में रहे हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है।

19 जून को अयोध्या आ सकते हैं मुख्यमंत्री

सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ 19 जून को श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंच सकते हैं। संभावित दौरे को देखते हुए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद में नया सवाल 1250 बहुमूल्य श्रीराम शिलाएं कहां गईं?

» धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे का दावा– तीन तालों में सुरक्षित रखी गई थीं सोने, चांदी और अष्टधातु की शिलाएं

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्याधाम। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच के बीच अब 1250 बहुमूल्य श्रीराम शिलाओं का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। हिंदू धर्म सेना के प्रमुख एवं पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने दावा किया है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश-विदेश से प्राप्त सोने, चांदी, अष्टधातु और रत्न जड़ित कुल 1250 शिलाएं वर्षों पहले सुरक्षित रखी गई थीं, लेकिन अब उनका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।संतोष दुबे के अनुसार, तत्कालीन रामजन्मभूमि न्यास अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास बताया करते थे कि इन शिलाओं में सबसे मूल्यवान शिला मॉरीशस से आई थी, जबकि मुंबई के एक व्यापारी द्वारा हीरे जड़ी शिला भेंट की गई थी। उनका दावा है कि इन शिलाओं में सर्वाधिक संख्या चांदी और सोने की शिलाओं की थी।बताया जा रहा है कि इन शिलाओं को परमहंस रामचंद्र दास के निर्देश पर चंपत राय की देखरेख में सुरक्षित रखा गया था। सुरक्षा के लिए जिस स्थान पर इन्हें रखा गया था, वहां तीन ताले लगाए गए थे। दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2002 तक इन शिलाओं की मौजूदगी की जानकारी थी।हालांकि इन आरोपों और दावों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एसआईटी फिलहाल दान और चढ़ावे से जुड़े प्रकरण की जांच कर रही है। यदि जांच के दायरे में यह विषय शामिल किया जाता है, तो बहुमूल्य श्रीराम शिलाओं के रिकॉर्ड, संरक्षण और वर्तमान स्थिति को लेकर भी तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल रामनगरी में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग आधिकारिक स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर बढ़ा सियासी और सामाजिक दबाव

» कांग्रेस, युवा कांग्रेस और हिंदू धर्म सेना ने उठाई निष्पक्ष जांच व एफआईआर की मांग

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

ज्ञापन देते कांग्रेस जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर जांच के बीच अब राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक ओर उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने थाना रामजन्मभूमि में प्रार्थना पत्र देकर दान एवं चढ़ावे से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत जांच की मांग की है, वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म सेना के प्रमुख एवं पूर्व कारसेवक संतोष दुबे ने भी रामजन्मभूमि थाने में लिखित शिकायत देकर नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है।

उधर जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी ने भी राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं स्वतंत्र जांच की मांग की है। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह और महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए पारदर्शी जांच आवश्यक है।

कांग्रेस नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अथवा नामित न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच समिति गठित करने, स्वतंत्र वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सीबीआई जांच कराने की मांग की है। वहीं युवा कांग्रेस ने जांच के दौरान बैंक अभिलेखों, लेखा दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की भी मांग उठाई है।राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच फिलहाल राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी कर रही है। ऐसे में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों की बढ़ती मांगों ने इस मामले को और अधिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से अभी तक किसी निष्कर्ष अथवा दोषी व्यक्ति के संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

सातवें मंगलवार पर नयाघाट में भंडारे का शुभारंभ, भाजपा नेता आलोक कुमार सिंह ने किया उद्घाटन

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या। नयाघाट क्षेत्र में सातवें मंगलवार के अवसर पर आयोजित भंडारे का शुभारंभ भाजपा नेता एवं अधिवक्ता आलोक कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और आयोजन की सराहना की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आलोक कुमार सिंह ने कहा कि भंडारे जैसे धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में जरूरतमंदों की सेवा और अन्नदान का विशेष महत्व है। ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ लोगों को एक-दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भाव का संदेश देते हैं।भंडारे में दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सभी के लिए भोजन और प्रसाद की समुचित व्यवस्था की गई थी। आयोजन समिति के सदस्यों और स्वयंसेवकों ने व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित किया।

इस अवसर पर संतोष गुप्ता, शैलेश यादव सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने भंडारे के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया।

ट्रंप पर बड़े हमले की साजिश नाकाम, व्हाइट हाउस को ड्रोन से उड़ाने की थी योजना

उपराष्ट्रपति, नेतन्याहू और एलन मस्क भी थे निशाने पर, एन्क्रिप्टेड चैट से खुला राज

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का पर्दाफाश करते हुए एक बड़े आतंकी हमले को विफल करने का दावा किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, ट्रंप के 80वें जन्मदिन के अवसर पर व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाले एक विशेष यूएफसी कार्यक्रम के दौरान हमले की योजना बनाई गई थी। इस मामले में विभिन्न राज्यों से पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

जांच में सामने आया है कि हमलावरों की योजना व्हाइट हाउस के उत्तरी हिस्से पर विस्फोटकों से लैस ड्रोन हमला करने की थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, उद्देश्य कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी और भगदड़ मचाना था। जैसे ही लोग जान बचाने के लिए बाहर निकलते, पहले से तैनात स्नाइपर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करते। इसके बाद हमलावरों द्वारा व्हाइट हाउस के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने की भी योजना बनाई गई थी।अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार, संदिग्धों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। जांचकर्ताओं को करीब 20 लोगों के बीच हुई एन्क्रिप्टेड चैट भी मिली है, जिसमें व्हाइट हाउस के नक्शे, सुरक्षा व्यवस्था, हमले के बाद छिपने के संभावित ठिकाने और फरार होने के रास्तों पर चर्चा की गई थी।एफबीआई की जांच में यह भी सामने आया है कि कथित साजिशकर्ताओं के निशाने पर केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं थे। सूची में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क तथा इजरायल समर्थक कई अमेरिकी सांसदों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों के नाम भी शामिल बताए गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, कथित भ्रष्टाचार और जेफ्री एपस्टीन प्रकरण से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराज थे। जांच में दावा किया गया है कि समूह के सदस्य मानते थे कि एपस्टीन से जुड़े प्रभावशाली लोगों को सार्वजनिक जीवन और सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए।एफबीआई के अनुसार, पूरे मामले का खुलासा 10 जून को मिली एक सूचना के बाद हुआ। जांच एजेंसियों को एक महिला ने जानकारी दी कि उसका 19 वर्षीय बेटा बड़ी मात्रा में हथियार खरीद रहा है और इंटरनेट पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद कथित साजिश की परतें खुलती चली गईं।फिलहाल एजेंसियां गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों और उनकी गतिविधियों की जांच में जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को हाल के वर्षों में सामने आई सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों में से एक बताया है।

बांग्लादेश में राम प्रतिमा पर विवाद, धमकियों के बाद निर्माण कार्य रोका गया

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

- कट्टरपंथी संगठनों की चेतावनी के बाद मंदिर समिति ने लिया फैसला
- सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए फिलहाल स्थगित किया गया निर्माण कार्य

नई दिल्ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े एक नए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। रंगपुर संभाग के पलाशबाड़ी क्षेत्र में भगवान राम की निर्माणाधीन प्रतिमा को लेकर बढ़े तनाव के बीच मंदिर प्रबंधन ने मूर्ति निर्माण का कार्य फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। मंदिर समिति का कहना है कि कट्टरपंथी संगठनों की ओर से लगातार मिल रही धमकियों और संभावित अशांति की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।मंदिर समिति के एक सदस्य ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इसी कारण भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण कार्य अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में परिस्थितियां अनुकूल होने और सभी पक्षों से चर्चा के बाद ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े उपदेशक ने सार्वजनिक रूप से निर्माणाधीन प्रतिमा का विरोध किया। सोशल मीडिया और सार्वजनिक सभाओं में दिए गए बयानों में उसने प्रशासन से प्रतिमा हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग स्वयं कार्रवाई करेंगे। इन बयानों के बाद

इलाके में तनाव का माहौल बन गया।स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, विवादित बयानों के बाद क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गईं। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि किसी भी प्रकार के टकराव या अप्रिय स्थिति से बचने के लिए निर्माण कार्य रोकने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।गौरतलब है कि बांग्लादेश में हाल के वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े धार्मिक स्थलों और गतिविधियों को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। ऐसे में पलाशबाड़ी की यह घटना एक बार फिर धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बहस का विषय बन गई है।

ईरान हुआ और ताकतवर! अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से ट्रंप की पीस डील पर उठे सवाल

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

खुफिया एजेंसियों का दावा- अब जब चाहे होर्मुज जलडमरुमध्य बंद कर सकता है ईरान

नई दिल्ली।अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की चर्चाओं के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक नई रिपोर्ट ने वॉशिंगटन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, हालिया संघर्ष के बाद ईरान पहले की तुलना में अधिक रणनीतिक रूप से मजबूत होकर उभरा है और अब उसके पास वैश्विक व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करने की क्षमता और बढ़ गई है।खुफिया सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अब किसी भी समय दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य, को बाधित करने की स्थिति में है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि युद्ध के बाद ईरान ने ऐसी सामरिक क्षमताएं विकसित कर ली हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि यदि परमाणु वार्ता विफल होती है तो ईरान, यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में भी तनाव पैदा कर सकता है। इससे दुनिया के दो प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग एक साथ प्रभावित हो सकते हैं।

हालांकि ट्रंप प्रशासन प्रस्तावित शांति समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन अमेरिका के भीतर इसके खिलाफ आलोचनाओं का दौर तेज हो गया है। कई रणनीतिक विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता अमेरिका की मजबूती नहीं बल्कि उसकी मजबूरी को दर्शाता है।विवाद उस समय

और बढ़ गया जब अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका पूरे संघर्ष के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर प्रभावी नियंत्रण बनाए हुए था। लेकिन जब पत्रकार मार्गरिट ब्रेनन ने उनसे सवाल किया कि यदि नियंत्रण पूरी तरह अमेरिका के पास था तो फिर जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना बातचीत का इतना अहम मुद्दा क्यों बना, तो हेगसेथ स्पष्ट जवाब देने के बजाय गोलमोल बातें करते नजर आए। उनके जवाब की सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में व्यापक आलोचना हुई।डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसदों ने भी प्रस्तावित समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी नेताओं ने इसे 'सरेंडर लेटर' तक करार देते हुए आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने झुककर एक कमजोर समझौता किया है। उनका कहना है कि यदि समझौते के बाद भी ईरान की सामरिक शक्ति बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, तो इसे अमेरिका की कूटनीतिक जीत नहीं कहा जा सकता।ऐसे में जहां एक ओर शांति समझौते को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट और घरेलू राजनीतिक विरोध इस डील की प्रभावशीलता तथा इसके दीर्घकालिक परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **सपना देवी** द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर-208012 (उप्र) से प्रकाशित। **संपादक: अनूप कुमार** **RNI No.:** UPHIN/2023/86739 ❍ **Email:** swarajindia2023@gmail.com ❍ Mob: 7800009853, ❍ **Website:** www.swarajindianews.com ❍ (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) **प्रधान संपादक: पुरुषोत्तम द्विवेदी**

ई-पेपर पढ़ने के लिए क्लिक करें
https://epaper.swarajindianews.com